International Educational Applied Research Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

E-ISSN No: 2456-6713

भारत में बेरोजगारी की समस्या : समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कारण और प्रभाव

श्रीमती ऋतु जैन
असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र)
चौधरी चरण सिंह राजकीय महाविद्यालय,
छपरौली (बागपत)
ई–मेल : ritu16081970@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15684483

सारांश

यह शोध पत्र भारत में बेरोजगारी की समस्या का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। बेरोजगारी न केवल एक आर्थिक संकट है, बल्कि यह सामाजिक असमानता, तनाव, हाशियेकरण और युवा पीढ़ी के आत्मविश्वास को भी गहराई से प्रभावित करने वाला एक बहुआयामी सामाजिक मुद्दा है। यह शोध पत्र बेरोजगारी के मूलभूत कारणों, जैसे जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा और कौशल के बीच असंतुलन, शहरीकरण, क्षेत्रीय विषमता, तकनीकी परिवर्तन, जाति और वर्ग आधारित भेदभाव, एवं नीति की विफलताओं का गहन अध्ययन करता है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह शोध पत्र बेरोजगारी को केवल रोजगार की अनुपलब्धता के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना और संस्थानों में व्याप्त गहराई से जुड़े संकट के रूप में देखता है। टाल्कॉट पारसन्स के संरचनात्मक– कार्यात्मक दृष्टिकोण से बेरोजगारी सामाजिक संस्थाओं की विफलता को इंगित करती है, जबकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण में यह पूँजीवादी व्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम है जिसमें श्रम को केवल लाभ की वस्तु मान लिया जाता है।

बेरोजगारी के प्रभावों में सबसे प्रमुख हैं आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक तनाव, आपराधिक प्रवृत्तियों में वृद्धि, मानसिक स्वास्थ्य की गिरावट, परिवारिक अस्थिरता और सामाजिक गतिशीलता का अवरुद्ध होना। यह शोध पत्र यह भी रेखांकित करता है कि बेरोजगारी का प्रभाव वर्ग, जाति, लिंग और क्षेत्रीय संदर्भों में भिन्न–भिन्न रूपों में उभरता है।

मुख्य शब्दः बेरोजगारी, सामाजिक संरचना, शिक्षा और कौशल, समाजशास्त्रीय विश्लेषण, मार्क्सवाद, सामाजिक असमानता, युवा संकट, वर्ग संघर्ष, नीति विफलता आदि।

प्रस्तावना

भारत जैसे विकासशील देश में बेरोजगारी की समस्या केवल आर्थिक असंतुलन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरे सामाजिक संकट का परिचायक भी है। यह समस्या सामाजिक संरचना, संस्थागत असफलताओं और नीति–निर्धारण की खामियों से उत्पन्न होती है, जो समाज के विभिन्न वर्गों विशेषकर युवाओं, महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों को असमान रूप से प्रभावित करती है। बेरोजगारी से न केवल आय का अभाव होता है, बल्कि यह व्यक्ति की सामाजिक पहचान, आत्मसम्मान और पारिवारिक संबंधों को भी गहराई से प्रभावित करती है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह नागरिकों को आजीविका का अधिकार प्रदान करे, लेकिन वास्तविकता यह है कि देश में करोड़ों लोग बेरोजगारी या अधूरी रोजगार व्यवस्था (underemployment) के शिकार हैं।

International Educational Applied Research Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

E-ISSN No: 2456-6713

राष्ट्रीय नमूना सर्वे कार्यालय (NSSO) की रिपोर्ट (2018–19) के अनुसार, भारत में बेरोजगारी दर 6.1 प्रतिशत थी, जो 45 वर्षों में सबसे अधिक थी। (1)

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेरोजगारी समाज में सामाजिक गतिशीलता को बाधित करती है। टाल्कॉट पारसन्स के अनुसार, समाज की संस्थाएँ जैसे शिक्षा, अर्थव्यवस्था और परिवार, यदि अपने उत्तरदायित्व को ठीक से नहीं निभातीं, तो सामाजिक विघटन उत्पन्न होता है। (2) बेरोजगारी उसी विघटन का परिणाम है जिसमें शिक्षा प्रणाली छात्रों को व्यावहारिक कौशल नहीं दे पा रही है और बाजार की आवश्यकताओं से उनका सामंजस्य टूट गया है।

वहीं मार्क्सवादी दृष्टिकोण बेरोजगारी को पूँजीवादी व्यवस्था की संरचनात्मक विफलता मानता है। मार्क्स के अनुसार, बेरोजगारी एक "रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर" का निर्माण करती है, जिससे पूंजीपति वर्ग श्रमिकों को सस्ते दर पर काम करने के लिए बाध्य कर सकता है। (3) इस प्रकार बेरोजगारी सामाजिक और आर्थिक शोषण का उपकरण बन जाती है।

भारत में बेरोजगारी के सामाजिक प्रभाव अनेक हैं गरीबी, मानसिक तनाव, आत्महत्या, अपराध की प्रवृत्ति, पारिवारिक विघटन और सामाजिक बहिष्करण। यह समस्या केवल आर्थिक नीतियों से नहीं सुलझ सकती, बल्कि इसके लिए समाजशास्त्रीय समझ, संस्थागत सुधार और सामाजिक समावेशन की आवश्यकता है।

इस शोध पत्र का उद्देश्य बेरोजगारी की समस्या का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है, जिसमें इसके कारणों और प्रभावों को गहराई से समझा जा सके। साथ ही यह शोध पत्र यह भी दर्शाता है कि किस प्रकार बेरोजगारी एक व्यापक सामाजिक समस्या बनकर समाज के विकास और स्थायित्व को प्रभावित करती है।

बेरोजगारी की समाजशास्त्रीय अवधारणा

बेरोजगारी एक ऐसी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति है जिसमें कार्य करने की इच्छा और योग्यता रखने वाले व्यक्ति को उपयुक्त रोजगार नहीं प्राप्त होता। यह स्थिति केवल आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि व्यक्ति की सामाजिक पहचान, प्रतिष्ठा और संबंधों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) बेरोजगारी को उस स्थिति के रूप में परिभाषित करता है जब कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए उपलब्ध हो, कार्य की तलाश कर रहा हो, लेकिन उसे कार्य न मिल पा रहा हो। (4)

भारत में बेरोजगारी के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं–

1. **खुले प्रकार की बेरोजगारी–** जब व्यक्ति पूर्ण रूप से बेरोजगार होता है। यह स्थिति आमतौर पर शिक्षित युवाओं में पाई जाती है।
2. **अप्रकट बेरोजगारी–** जब अधिक लोग किसी कार्य में लगे होते हैं, लेकिन उनकी उत्पादकता शून्य होती है। यह स्थिति मुख्यतः कृषि क्षेत्र में देखी जाती है।
3. **मौसमी बेरोजगारी–**यह बेरोजगारी केवल एक विशेष मौसम तक सीमित होती है, जैसे कृषि में बुआई या कटाई के समय।
4. **आंशिक बेरोजगारी–** जब व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता से कम स्तर का कार्य मिलता है।
5. **शहरी बेरोजगारी–** तेजी से बढ़ते शहरीकरण और सीमित औद्योगिक अवसरों के कारण यह समस्या दिन–ब–दिन बढ़ रही है।

International Educational Applied Research Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

E-ISSN No: 2456-6713

बेरोजगारी का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बेरोजगारी को केवल एक आर्थिक असंतुलन नहीं, बल्कि सामाजिक संस्थाओं की विफलता के रूप में देखा जाता है। यह संस्थाएँ जैसे शिक्षा, परिवार, राज्य और अर्थव्यवस्था, व्यक्ति के समाजीकरण, कार्य–योग्यता और समुचित अवसर प्रदान करने में यदि असफल रहती हैं, तो बेरोजगारी जैसी सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

संरचनात्मक–कार्यात्मक दृष्टिकोण के अनुसार बेरोजगारी एक अस्थायी विकृति है जो समाज में असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। टालकॉट पारसन्स और एमिल दुर्खीम जैसे विचारकों के अनुसार, बेरोजगारी सामाजिक संस्थाओं के अपेक्षित कार्य निष्पादन में असफलता का संकेत है। (5) जब शिक्षा प्रणाली समाज की औद्योगिक मांगों के अनुरूप मानव संसाधन तैयार नहीं कर पाती, तब यह बेरोजगारी को जन्म देती है।

संघर्ष सिद्धांत के अनुसार, बेरोजगारी पूंजीवादी व्यवस्था की स्वाभाविक उपज है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि पूंजीपति वर्ग एक 'रिज़र्व आर्मी ऑफ लेबर' बनाए रखता है ताकि श्रमिकों पर दबाव बना रहे और उन्हें न्यूनतम मजदूरी पर कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सके। (6) इस प्रकार बेरोजगारी केवल अवसरों की कमी नहीं, बल्कि वर्गीय शोषण का प्रतीक बन जाती है।

प्रतीकात्मक अन्तःक्रिया सिद्धांत बेरोजगारी को सामाजिक पहचान के संकट के रूप में देखता है। बेरोजगार व्यक्ति अपने आत्म–सम्मान और सामाजिक स्थिति को खोने लगता है, जिससे अवसाद, आत्मग्लानि और सामाजिक अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है। एर्विंग गोफमैन के अनुसार, "सामाजिक पहचान का संकट व्यक्ति को सामाजिक मंच पर अपनी भूमिका खोने के समान है। (7)

इस प्रकार, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण बेरोजगारी को एक समग्र सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखता है, जिसमें आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और संस्थागत कारकों की अंतःक्रिया होती है। यह दृष्टिकोण हमें यह समझने में सहायक होता है कि बेरोजगारी केवल रोजगार की अनुपलब्धता नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना और मूल्य–प्रणाली में व्याप्त असंतुलन का परिणाम है।

भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण

भारत की जनसंख्या में तीव्र गति से हुई वृद्धि ने रोजगार के अवसरों पर अत्यधिक दबाव डाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.3 अरब से अधिक है और यह विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। (8) जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में रोजगार सृजन न होने के कारण श्रमिकों की आपूर्ति में असंतुलन उत्पन्न होता है। इस स्थिति में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के अनपढ़ और अर्धशिक्षित युवा बेरोजगारी का शिकार होते हैं। संसाधनों की सीमितता और सरकारी अवसरों की संख्या में कमी इस संकट को और गहरा करती है।

शिक्षा प्रणाली और कौशल विकास का अंतर

भारत की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली अभी भी मुख्यतः सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित है, जबकि उद्योगों को ऐसे युवाओं की आवश्यकता होती है जिनमें व्यवहारिक कौशल, तकनीकी दक्षता और नवाचार की क्षमता हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP, 2020) इस अंतर को पाटने की दिशा में प्रयासरत है, किंतु वास्तविक कार्यान्वयन अभी भी सीमित है। एक रिपोर्ट के अनुसार, "भारत के केवल 20 प्रतिशत स्नातक ही उद्योगों द्वारा 'रोजगार योग्य' माने जाते हैं। (9) इस कौशल अंतर ने शिक्षित बेरोजगारी (Educated Unemployment) को जन्म दिया है, जहाँ डिग्री तो है, लेकिन रोजगार नहीं।

International Educational Applied Research Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

E-ISSN No: 2456-6713

क्षेत्रीय और शहरी–ग्रामीण विषमता

भारत में रोजगार के अवसर क्षेत्रीय रूप से असमान हैं। महानगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार की संभावना अधिक होती है, जबकि दूर–दराज के ग्रामीण या पिछड़े इलाकों में नौकरियाँ कम उपलब्ध होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर बड़े पैमाने पर पलायन होने से शहरी बेरोजगारी बढ़ जाती है, जिससे झुग्गी–झोपड़ियाँ, असंगठित मजदूरी और जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आती है। साथ ही, यह असमानता सामाजिक अशांति को भी जन्म देती है। (10)

सामाजिक वर्ग, जाति और लिंग आधारित भेदभाव

भारत में सामाजिक भेदभाव बेरोजगारी की एक गंभीर जड़ है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम अल्पसंख्यक और महिलाएँ रोजगार प्राप्त करने में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करते हैं। जातिगत भेदभाव, खासकर निजी क्षेत्र में, अप्रत्यक्ष रूप से अवसरों से वंचित करता है। महिलाओं के संदर्भ में, कार्यस्थल पर भेदभाव, पारिवारिक प्रतिबंध और सामाजिक दृष्टिकोण उनकी कार्यक्षमता को सीमित करता है। NSSO की एक रिपोर्ट के अनुसार, "कामकाजी महिलाओं की भागीदारी 2022 में केवल 20.3 प्रतिशत थी, जो कि विश्व औसत से बहुत कम है। (11) यह आंकड़ा दर्शाता है कि लिंग आधारित असमानता रोजगार के क्षेत्र में भी विद्यमान है।

तकनीकी परिवर्तन और स्वचालन

डिजिटल क्रांति और स्वचालन (Automation) ने एक ओर उच्च कौशल वाले युवाओं को नए अवसर प्रदान किए हैं, वहीं दूसरी ओर परंपरागत नौकरियों को समाप्त कर बेरोजगारी को बढ़ावा भी दिया है। बैंकिंग, खुदरा, परिवहन और निर्माण जैसे क्षेत्रों में ऑटोमेशन के कारण कम पढ़े–लिखे और अर्ध–कुशल श्रमिकों के लिए अवसर सीमित हो गए हैं। रिचर्ड बाल्डविन के अनुसार, "तकनीक नौकरियों को समाप्त नहीं करती, बल्कि उनके स्वरूप को बदल देती है। (12) भारत में इस परिवर्तन के लिए तैयार न होना बेरोजगारी की नई चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहा है।

सरकारी योजनाओं की विफलताएँ और नीतिगत चुनौतियाँ

भारत सरकार ने रोजगार सृजन के उद्देश्य से अनेक योजनाएँ प्रारंभ की हैं, जैसे– MGNREGA (2005), स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) और आत्मनिर्भर भारत अभियान। इन योजनाओं के बावजूद बेरोजगारी के आँकड़े कम नहीं हुए हैं। मुख्य समस्याएँ हैं– योजनाओं का असमान कार्यान्वयन, जमीनी स्तर पर निगरानी की कमी, भ्रष्टाचार और लाभार्थियों तक पहुँच का अभाव।

उदाहरणस्वरूप, MGNREGA में कार्य दिवसों की सीमित संख्या और समय पर भुगतान न होना इसे प्रभावी विकल्प नहीं बना पाया। इसी प्रकार, स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों में प्रशिक्षण तो हुआ, परंतु उपयुक्त रोजगार नहीं मिल पाया। नीति आयोग की एक रिपोर्ट (2022) में स्वीकार किया गया कि "रोजगार सृजन की गति आर्थिक विकास के अनुरूप नहीं रही है। (13)

बेरोजगारी के सामाजिक प्रभाव

बेरोजगारी का सबसे प्रत्यक्ष और व्यापक प्रभाव आर्थिक असुरक्षा के रूप में सामने आता है। जब व्यक्ति के पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं होता, तो उसकी जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कठिन हो जाती है। यह स्थिति केवल व्यक्तिगत संकट नहीं, बल्कि समाज के बड़े वर्ग में व्याप्त असमानता और संसाधनों की अनुचित वितरण प्रणाली की ओर भी संकेत करती

International Educational Applied Research Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

E-ISSN No: 2456-6713

है। बेरोजगारी के कारण गरीबी की चक्रव्यूह में फंसे परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसी बुनियादी सेवाओं तक भी पहुँच नहीं मिल पाती। योजना आयोग की रिपोर्ट (2011) के अनुसार भारत की लगभग 22 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है और बेरोजगारी इस आंकड़े का प्रमुख कारण है। (14)

पारिवारिक तनाव और घरेलू कलह

बेरोजगारी का प्रभाव केवल आर्थिक स्तर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पारिवारिक संबंधों को भी प्रभावित करता है। बेरोजगार व्यक्ति की आत्म–संवेदना में कमी आती है, जिससे तनाव, चिड़चिड़ापन और आत्मग्लानि जैसे भाव उत्पन्न होते हैं। इसका परिणाम पारिवारिक संबंधों में कलह, मतभेद और कभी–कभी घरेलू हिंसा तक के रूप में प्रकट होता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट (UNDP, 2021) के अनुसार, बेरोजगारी से पीड़ित परिवारों में वैवाहिक कलह और तलाक की दर अधिक पाई गई है। विशेषकर पुरुष बेरोजगार होने पर पारिवारिक उत्तरदायित्वों का तनाव स्त्रियों पर और अधिक बढ़ जाता है, जिससे लिंग आधारित तनाव उत्पन्न होते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य और अवसाद

बेरोजगारी और मानसिक स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध होता है। लंबे समय तक बेरोजगार रहने वाले व्यक्ति में आत्म–संमेलन की कमी, सामाजिक अलगाव और हीन भावना उत्पन्न होती है, जो अवसाद और चिंता जैसे मानसिक विकारों को जन्म देती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रत्येक चार में से एक व्यक्ति मानसिक तनाव का शिकार है और बेरोजगारी इस स्थिति को बढ़ाने वाला एक प्रमुख कारक है। समाजशास्त्री एर्विंग गोफमैन ने इसे "सामाजिक छवि के ह्रास" से जोड़ा है, जिसमें व्यक्ति समाज में अपनी भूमिका खो बैठता है। (15)

सामाजिक अपराध, ड्रग्स और आपराधिक प्रवृत्तियाँ

जब व्यक्ति रोजगार से वंचित होता है और सामाजिक संरचना उसे वैध आय के अवसर प्रदान नहीं कर पाती, तो वह अवैध गतिविधियों की ओर प्रवृत्त हो सकता है। चोरी, डकैती, ड्रग्स, मानव तस्करी और अन्य आपराधिक कृत्य बेरोजगारी से उत्पन्न निराशा और हताशा के परिणाम हो सकते हैं। NCRB की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 15 से 29 वर्ष के युवाओं द्वारा किए गए अपराधों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिनमें अधिकांश का संबंध बेरोजगारी या आर्थिक अभाव से था। (16)

युवा वर्ग में निराशा और पलायन

युवा वर्ग किसी भी राष्ट्र का भविष्य होता है, किंतु जब उन्हें उपयुक्त अवसर नहीं मिलते तो उनमें असंतोष, हताशा और निराशा घर कर जाती है। बेरोजगारी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त युवा भी छोटे–मोटे या अप्रासंगिक कार्य करने को विवश हो जाते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास टूटता है। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी केंद्रों और भारत से विदेशों की ओर पलायन बढ़ता है। यह 'ब्रेन ड्रेन' भारत जैसे विकासशील देश के लिए सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से गंभीर समस्या बन चुका है।

सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक बहिष्करण

बेरोजगारी सामाजिक गतिशीलता को बाधित करती है। विशेष रूप से निम्न वर्ग और हाशिए पर स्थित समुदायों के लिए यह समस्या और भी गहरी होती है। जब समाज में अवसरों की असमानता होती है, तो एक वर्ग विशेष सामाजिक सीढ़ी चढ़ने में

International Educational Applied Research Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

E-ISSN No: 2456-6713

असफल रहता है और वह स्थायी रूप से हाशिए पर चला जाता है। बेरोजगारी केवल आय का संकट नहीं, बल्कि सामाजिक पहचान, सम्मान और भागीदारी का संकट भी बन जाती है। यह स्थिति सामाजिक बहिष्करण (Social Exclusion) को जन्म देती है, जिसमें व्यक्ति केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से भी अलग–थलग पड़ जाता है।

सरकार की भूमिका और योजनाएँ

भारत सरकार ने बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए समय–समय पर विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम आरंभ किए हैं। इनका उद्देश्य न केवल रोजगार सृजन है, बल्कि सामाजिक समावेशन, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता की भावना को भी बढ़ावा देना है। इन योजनाओं का सामाजिक पहुँच और प्रभाव समाज के विभिन्न वर्गों पर गहराई से प्रभाव डालता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA)

MGNREGA (2005) को भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम के रूप में लागू किया, जिसके अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिन का श्रम आधारित रोजगार प्रदान करने की गारंटी दी जाती है। इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और अप्रकट बेरोजगारी को कम करने में सहायता की है। खासकर महामारी के दौरान यह योजना प्रवासी मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए जीवन रक्षक सिद्ध हुई। (17) समय पर भुगतान न होना, कार्य की अस्थिरता और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसी समस्याएँ इसकी प्रभावशीलता को सीमित करती हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

PMKVY का उद्देश्य युवाओं को उद्योग के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण देना और उन्हें रोजगार योग्य बनाना है। 2015 में शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक लाखों युवाओं को अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण दिया गया है। परंतु कई रिपोर्टों में यह देखा गया है कि प्रशिक्षण के बाद युवाओं को अपेक्षित रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिससे योजना की सामाजिक स्वीकार्यता प्रभावित हुई है। (18)

स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया

इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य युवाओं को पारंपरिक नौकरी से हटकर उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित करना है। स्टार्टअप इंडिया (2016) के अंतर्गत टैक्स में छूट, ऋण सुविधा और नवाचार के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। वहीं स्टैंडअप इंडिया (2016) विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इन योजनाओं ने नई सोच को जन्म दिया है, परंतु ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में सूचना की कमी, पूँजी तक पहुँच की कठिनाई और तकनीकी ज्ञान के अभाव ने इनके सामाजिक प्रभाव को सीमित किया है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान

कोविड–19 महामारी के दौरान घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान (2020) का उद्देश्य देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs) को प्रोत्साहन दिया गया है, जिससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिला है। यह अभियान 'वोकल फॉर लोकल' की अवधारणा पर आधारित है और इसका उद्देश्य देश के भीतर रोजगार के अवसरों को सृजित करना है।

International Educational Applied Research Journal
A Multi-Disciplinary Research Journal
E-ISSN No: 2456-6713

सामाजिक पहुँच और प्रभाव का मूल्यांकन

इन योजनाओं की सामाजिक पहुँच का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि इनका प्रभाव क्षेत्र, वर्ग, जाति और लिंग के अनुसार भिन्न है। योजनाएँ नीति स्तर पर प्रभावी हैं, किंतु जमीनी क्रियान्वयन, निगरानी व्यवस्था, प्रशिक्षण की गुणवत्ता और लाभार्थियों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर गंभीर चुनौतियाँ हैं।

अतः यह आवश्यक है कि इन योजनाओं के मूल्यांकन को केवल आँकड़ों तक सीमित न रखकर, उनकी सामाजिक प्रभावशीलता, समावेशन और स्थायित्व को भी ध्यान में रखा जाए ताकि बेरोजगारी की समस्या को सार्थक ढंग से संबोधित किया जा सके।

निष्कर्ष

यह शोध पत्र "भारत में बेरोजगारी की समस्या : समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कारण और प्रभाव" विषय पर केंद्रित रहा, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि बेरोजगारी केवल आर्थिक नहीं, बल्कि एक जटिल सामाजिक समस्या है। इसके कारण बहुआयामी हैं, जो शिक्षा प्रणाली, जनसंख्या दबाव, सामाजिक भेदभाव, क्षेत्रीय विषमता, तकनीकी परिवर्तन और सरकारी नीतियों की व्यावहारिक विफलताओं से जुड़े हुए हैं। बेरोजगारी समाज की संस्थागत असफलता का परिणाम है। जब शिक्षा प्रणाली व्यावहारिक कौशल प्रदान नहीं कर पाती, जब राज्य आर्थिक विकास को सामाजिक न्याय से नहीं जोड़ पाता, तब बेरोजगारी समाज में विषमता, अपराध, मानसिक तनाव, पारिवारिक विघटन और सामाजिक बहिष्करण जैसी समस्याओं को जन्म देती है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, बेरोजगारी को केवल रोजगार की अनुपलब्धता नहीं माना जा सकता, बल्कि यह सामाजिक पहचान, आत्मसम्मान और भागीदारी के अवसरों की कमी को भी दर्शाता है। पारसन्स का संरचनात्मक– कार्यात्मक दृष्टिकोण इसे संस्थाओं की कार्यात्मक विफलता मानता है, जबकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण इसे वर्गीय शोषण और पूंजीवादी नियंत्रण का उपकरण बताता है।

इस लेख में यह भी सामने आया कि सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएँ, जैसे MGNREGA, PMKVY, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान बेरोजगारी की समस्या के समाधान की दिशा में प्रयासरत हैं। लेकिन इन योजनाओं की सफलता क्षेत्रीय असमानता, निगरानी व्यवस्था, प्रशासनिक दक्षता और सामाजिक जागरूकता पर निर्भर करती है। बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए बहुस्तरीय रणनीति की आवश्यकता है। इसमें शिक्षा और कौशल विकास का पुनर्गठन, सामाजिक समावेशन की नीति, संस्थागत पारदर्शिता और नीति–निर्माण में हाशिए पर स्थित वर्गों की भागीदारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बेरोजगारी को केवल एक आँकड़ा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के संदर्भ में एक चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए।

संदर्भ

1. मोसपीए 2019ए पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वेए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयए नई दिल्लीए पृ०सं० 12
2. पार्सन्सए टीए 1951ए द सोशल सिस्टम फ्री प्रेस न्यूयॉर्कए पृ०सं० 273
3. मार्क्स के 1867 कैपिटल वॉल्यूम ᴾ प्रोग्रेस पब्लिशर्सए मॉस्कोए पृ०सं० 450
4. आईएलओए 2020 वर्ल्ड एंप्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुकए जेनेवाए पृ०सं० 15
5. पार्सन्सए टीए 1951ए द सोशल सिस्टमए फ्री प्रेसए न्यूयॉर्कए पृ०सं० 273
6. मार्क्सए केण 1867ण कैपिटल वॉल्यूम ᴾ प्रोग्रेस पब्लिशर्सए मॉस्कोए पृ०सं० 447

International Educational Applied Research Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

E-ISSN No: 2456-6713

7. गोफमैनए ईए 1959ए द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ एंकर बुक्सए न्यूयॉर्कए पृ०सं०, 67
8. भारत की जनगणना 2011ए भारत सरकार नई दिल्ली
9. इंडिया स्किल्स रिपोर्टए 2022 व्डीबोक्सए सीआईआईए पृ०सं० 22
10. ड्रेज़ए जेण एवं सेनए एण 2013 अनसर्टेन ग्लोरी इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन्सए पेंगुइन बुक्सए नई दिल्लीए पृ०सं० 57
11. पीएलएफएसए 2022 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयए नई दिल्ली
12. बाल्डविनए आरण 2019ण द ग्लोबॉटिक्स अपडीवलए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेसए पृ०सं० 43
13. नीति आयोगए 2022ए न्यू इंडिया के लिए रणनीतिए पृ०सं० 74
14. योजना आयोगए भारत सरकार 2011ए गरीबी का आकलनए पृ०सं० 7
15. गोफमैनए ईए 1959ए द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफए एंकर बुक्सए पृ०सं० 87
16. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरोए 2021ए नई दिल्लीए पृ०सं० 211
17. ग्रामीण विकास मंत्रालय 2021 वार्षिक रिपोर्टए भारत सरकारए नई दिल्लीए पृ०सं० 46
18. एनएसडीसीए 2022ए स्किल इंडिया प्रगति रिपोर्टए नई दिल्लीए पृ०सं० 35